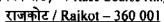


ः : आयुक्तः (अपील्स) का कार्यालय , वस्तुं एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2rd Floor, GST Bhavan. रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in



रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230164SX000021792F

क अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.

फाइनसंब्या/ मूलआदेशसं / //File No. OIO No.

52/D/2021-22

दिनांक/ Date

19-01-2022

ख अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-398-2022

आदेश का दिनांक /

V2/76/RAJ/2022

27.12.2022

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

03.01.2023

Date of Order:

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर , राजकोट / जामनगर / गांधीक्षाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से मृजित : /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

वपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Bhudarbhai Becharbhai Detroja, Behind Gayatri Nagar, Near Randev Mandir, Ravapar Road, Morbi-363641.

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति कोई व्यक्ति निम्नलिखित सरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समझ अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त विधिनियम , 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखिनत जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुन्क, केन्द्रीय उत्पादन शुन्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट म्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई विल्ली, को की जानी चाहिए !/

The special beach of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुरूक केंद्रीय उत्पाद शुरूक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, ,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावी जहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चौहिए !/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- I(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चाप प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के माथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक जयंदा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो कमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अपना 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का मुगतान, मंबिधेत अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नीम से किसी भी सार्वीजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित शुल्क का मुगतान, बैंक की उसे शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए जावेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-. Rs. 10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र 8.ए.-5में चार प्रतियाँ में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम से के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ज्याज की माँग अपेत स्वाया गया जुमाना, रुपए 5 लाख या उससे कुछ, 5 लाख रुपए वा 50 लाख रुपए तुक अथवा 10,000/- रुपये आपेता 10,000/- रुपये का निर्धारित अमा शुक्त की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुक्त का भूगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भूगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्वित है। स्थमन आदेश (स्टे ऑडर) के लिए आवेदन-एव के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्त जमां का निर्धार संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्वित है। स्थमन आदेश (स्टे ऑडर) के लिए आवेदन-एव के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्त जमां का निर्धार संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्वित है। स्थमन आदेश (स्टे ऑडर) के लिए आवेदन-एव के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्त जमां करना बीचा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be companied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be companied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Astrictant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is attacked. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

- विस्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ अनुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्त अधवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्त हारा पारित अदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और अनुक्त हारा सहायक अयुक्त अपवा उपायक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्त सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने निर्देश देन वो बोदेश की प्रति भी माथ में संस्त्र करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस अवश्य के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/मेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुमांना विवादित है, या जुमांना, जब केवल जुमांना विवादित है, का भुगतान किया जाए, अशर्त के इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपिक्षेत देय राशि दस करोड़ कएए से अधिक न हो।

 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

 (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम

 (ii) सेनवेट जमा की शी गई गलत राशि

 (iii) सेनवेट जमा की शी गई गलत राशि

 (iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

 बशर्ते यह के इस धारा के आवधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंश से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दिचाराधीन समक्षत कर्जी एवं अपील को लाग नहीं होगे। (ii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान किसीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दिचाराधीन स्थान अज़ीं एवं अपील को लागू नहीं होगे!/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

- मारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :
 Revision application to Government of India:
 इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन :
 इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन ईकाई वित्त समस्त्रों में हैं कि उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रयमुपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई वित्त मंत्रालय, राजस्व विकाग, बीची मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।

 A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid: (C)
- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, वहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पार्गमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक खंडार गृह से दूसरे अंडार गृह पारगमन के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी in case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे मान के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे मान पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / in case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भूगतान के लिए जो ड्यूटी केहीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे अदेश जो आपक (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न-2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अधवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। िएनोहीं of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance.(No.2) Act, 1998. (iv)
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त अवेदन के साथ मूल आदेश के अपील आदेश की दो प्रतियां सलग्र की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के सहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति सलग्र की जानी चाहिए। / (v) The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OlO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्निषिक्षत निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संक्षप्र रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुस्क का मुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए . भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति जपीलीय नवाधिकरण को एक अपील यो केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is lilled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थयन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चौहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाल नियमों की और मी ध्यान आकवित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Kules, 1982. (F)
- उच्च अपीलीय प्राप्तिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्यी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

M/s Bhudarbhai Becharbhai Dtroja, Behind Gayatrinagar, Near Randev Mandir, Ravapar Road, Morbi-363 641(hereinafter referred to as appellant) has filed appeal No.V2/76/RAJ/2022 'against Order-in-Original No. 52/D/2021-22 dated 19.01.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Morbi-I (hereinafter referred to as 'adjudicating authority'):-

- 2. The facts of the case, in brief, are that a show cause notice was issued to the appellant demanding service tax of Rs.4,24,390/- on the basis of data received from Income Tax Department. The adjudicating authority has decided the issue vide the impugned order and confirmed the demand. He imposed penalty of Rs.4,24,390/- under Section 78, Rs.10,000/- under Section 771)(a), Rs.10,000/- and under Section 77(2) of the Finance Act, 1994 on the appellant.
- 3. Being aggrieved, the appellant has filed present appeal wherein they contended that appellant is a proprietary concern and provided service of erection of HL, LT line, maintenance, fabrication etc which is a 'works contract' service. They contended that as per Sr.No.9 of Notification No.30/2012-ST dated 20.06.2012, the appellant is liable to pay only 50% of service tax liability as the service is provided to PGVCL, a company owned by Government of Gujarat. The appellant submitted that the value on which the service tax payable by them is below threshold of Rs.10 lakhs as per Notification No.33/2012-ST as computed below:

Period	Gross Amount	50% value due under RCM	Taxable value after abatement	Service Tax payable	
2014-15	3433584	1716792	686717	Nil as the value below Rs.10 lakhs	

The appellant also submitted that PGVCL is a company established by Gujarat Government having 100% ownership and hence they are eligible for exemption as per Sr. No.12(a) of Notification No.25/2012-ST. The appellant also submitted that cum-tax benefit should be granted to them as per Section 67(2) of the Finance Act, 1994. The appellant relied upon a catena of decisions in support of their claim to avail abatement on works contract service as per Rule 2A(ii) of Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006.

The appellant further submitted that show cause notice dated 28.09.2020 was issued for the demand of service tax for the period 2014-15 and the period of limitation for the first half year was already completed.

i Devkaran P. Kanzaria, Consulțant appeared for personal hearing

Page 3 of 5

on 22.12.2022 and reiterated the submissions made in the grounds of appeal. He submitted that the appellant is a contractor to M/s PGVCL and the work done by him is exempt from service tax. He requested to allow 10 days' time for submission of further arguments and supporting documents in this regard. He requested to drop the order-in-original.

- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the Appellants. The moot question to be decided in the present appeal is whether the appellant is liable to pay service tax on the work carried out by them.
- 6. I find that the appellant had made the argument before the adjudicating authority that they had provided service related to repair and maintenance of PGVCL, which is a 'Government Authority' and accordingly the services provided by them were covered under Notification No.25/2012-ST dated 20.06.2012. The adjudicating authority, in the impugned order, held that PGVCL is a body corporate incorporated under Companies Act, 2013 and the service provided by PGVCL are not covered under the works specified under Articles 243W of the Constitution of India and hence the service is not covered under Sr. No.12(a) of Notification No.25/2012-ST.
- 7.1 In the present appeal, the appellant had made another argument that the services provided by them are 'work contract service' and as per Sr.No.9 of Notification No.30/2012-ST dated 20.06.2012, liable to pay only 50% of service tax liability. The appellant also contended that there is no service tax liability as the value of service after deducting 50% of value payable under RCM.
- 7.2 In this regard, I find that the computation done by the appellant giving the service tax liability as per the table above is not correct. As per Notification number, the percentage of service tax payable by provider and recipient of certain services are specified and not the value of service, contrary to the contention raised by the appellant. The correct way to determine the service tax liability should be as under:

Gross Amount	Abatement (%)	Abatement value	Taxable value after abatement	Rate of service tax	Service Tax payable
1	2	3=(1x2/100)	4=(1-3)	5	6= (4x5/100)

7.3 However, I find that the appellant has made the said contention first time in appeal and it was not raised before the adjudicating authority. Therefore, the matter needs to be examined at the end of adjudicating authority and a finding in this regard is required to be recorded by the adjudicating authority after equiting the evidences. In view of the above, I deem it proper to remand back

Page 4 of 5

the matter to the adjudicating authority to pass a fresh order after considering the submissions of the appellant about the liability to pay service tax under 'works contract' service and the issue of limitation raised.

- In view of above, I set aside the impugned order and allow the appeal by way of remand to the adjudicating authority. The adjudicating authority is directed to pass a fresh order within 30 days from the receipt of this order and following the principles of natural justice. The appellant shall produce all the relevant documents and evidences before the adjudicating authority.
- अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है । ९.

The appeal filed by the Appellant is disposed off as above. 9.

सत्यापित / Attested

Superintendent

Rajkot

(शिव प्रताप सिंह) SHIV PRATAP SINGH) Central GST (Appeals) आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में मेस्सेर्स भुदरभाई बेचारभाई डेत्रोजा बिहाइंड गायत्री नगर नियर रनदेव मंदिर रवापर रोड, मोरबी-363 641

To M/s Bhudarbhai Becharbhai Detroja, Behind Gayatrinagar, Near Randev Mandir,

Ravapar Road, Morbi-363 641

प्रतिलिपि:-

1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुक्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।

2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट ।

3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल मोरँबी-। .

4) गार्ड फ़ाइल।

